

Daily Current Affairs

Date : 04 July, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान में HPCL के रिटेल आउटलेट्स
2.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. प्रथम भल्ला : यूके संसद में सम्मानित 2. सिरोही जिले का 'रोशनी अभियान' 3. 'राजस्थान में सहकारिता' पुस्तक का विमोचन
3.	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 2026
4.	VB-G RAM G अधिनियम
5.	16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन
6.	नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन
7.	बोरजुली आर्द्रभूमि
8.	विक्रम-1, भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट
9.	गगन: भारत के आकाश में सटीक नेविगेशन
10.	हरित अमोनिया और मेथनॉल

--:1:--



UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213



राजस्थान परिदृश्य



राजस्थान में HPCL के रिटेल आउटलेट्स



मुख्य बिन्दु:

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में बालोतरा के पचपदरा (मंडापुरा) में HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन किया गया।
- इसके साथ ही, राजस्थान सरकार ने पूरे राज्य में ₹400 करोड़ के निवेश से 304 नए HPCL पेट्रोल पंप स्थापित करने की एक बड़ी विस्तार योजना को मंजूरी दी।
- पचपदरा में खुले इस नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट (Fuel Station) में उन्नत ईंधन सुविधाओं के साथ-साथ आधुनिक फूड प्लाजा और स्वच्छ जनसुविधाएं जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) भारत की एक अग्रणी महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और यह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) की एक सहायक कंपनी है। भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में HPCL का लगभग 20.5% बाजार हिस्सा है।

न्यूज़ इन शॉर्ट्स

क्र. सं.	न्यूज़
1.	प्रथम भल्ला : यूके संसद में सम्मानित ■ युवा सामाजिक कार्यकर्ता प्रथम भल्ला को लंदन में यूके संसद में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया। ■ यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें सामाजिक विकास, सामुदायिक सशक्तीकरण और समाज कल्याण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। ■ प्रथम भल्ला ने राजस्थान विश्वविद्यालय से MBA किया है और उनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा सेंट पॉल्स स्कूल, अजमेर से हुई है।
2.	सिरोही जिले का 'रोशनी अभियान' ■ सिरोही जिले में किशोरियों एवं बालिकाओं में एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से 'रोशनी अभियान' का संचालन किया जा रहा है। ■ अभियान का प्रथम चरण : 15 जुलाई से 15 अक्टूबर, 2026 तक। ■ मुख्य उद्देश्य: जिले की कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना, हीमोग्लोबिन (Hb) की जांच करना और उनके पोषण में सुधार करना है। ■ गतिविधियां: अभियान के तहत मासिक हीमोग्लोबिन स्क्रीनिंग, आयरन-फोलिक एसिड (IFA) टैबलेट, एल्बेंडाजोल (कृमि मुक्ति दवा) और मल्टीविटामिन का वितरण किया जा रहा है।
3.	'राजस्थान में सहकारिता' पुस्तक का विमोचन ■ सहकारिता आंदोलन के राष्ट्रीय स्वरूप को केंद्र में रखकर सहायक रजिस्ट्रार डॉ. जयप्रकाश यादव द्वारा रचित पुस्तक 'राजस्थान में सहकारिता' का विमोचन अपेक्स बैंक स्थित सभागार में सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम कृषक सम्मान समारोह के दौरान आयोजित हुआ।



राष्ट्रीय परिदृश्य



कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 2026



चर्चा में क्यों?

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कार्यान्वयन के तहत, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 2026 को अधिसूचित किया है, जो ईपीएफ योजना, 1952 का स्थान लेगी।



मुख्य बिन्दु:

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 2026

- कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 2026 भारत की नई वैधानिक भविष्य निधि योजना है जो मौजूदा योजना का स्थान लेगी।
- मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों को बरकरार रखते हुए भविष्य निधि प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अधिसूचित किया गया है।
- **नोडल मंत्रालय:** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।
- **कार्यपालक प्राधिकारी:** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

उद्देश्य:

- कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और सेवानिवृत्ति बचत प्रदान करना।
- आधुनिक भविष्य निधि ढांचे के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को लागू करना।

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

VB-G RAM G अधिनियम



चर्चा में क्यों?

- विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025, 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है।



मुख्य बिन्दु:

- हाल ही में, भारत ने ग्रामीण रोजगार नीति को आधुनिक बनाने के लिए विकसित भारत @2047 के अनुरूप एमजीएनआरईजीए, 2005 को वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 (विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी) से प्रतिस्थापित किया है।

वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025

- इसे दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित किया गया था और यह दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), 2005 का स्थान लिया है।
- यह एक स्वतंत्र कल्याणकारी हस्तक्षेप से ध्यान हटाकर विकास और लचीले बुनियादी ढांचे के एक एकीकृत साधन पर केंद्रित करता है।

Viksit Bharat G RAM G Act 2025



FOUR PRIORITY THEMATIC AREAS

WATER SECURITY

Strengthening water security across rural regions



CORE RURAL INFRASTRUCTURE

Ensuring better basic amenities and improved access to services



LIVELIHOOD RELATED INFRASTRUCTURE

Supporting sustainable livelihoods, value addition and diversified rural income opportunities



SPECIAL WORKS FOR EXTREME WEATHER EVENTS

Creating climate resilient villages and disaster preparedness



Source: Ministry of Rural Development

VB-G RAM G की प्रमुख विशेषताएं

- **गारंटीकृत वेतन रोजगार दिवसों में वृद्धि:** वीबी-जी आरएएम जी अधिनियम के द्वारा कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया है।
- **कृषि सीजन के दौरान रोजगार गारंटी में विराम :** वीबी-जी आरएएम जी योजना के तहत कृषि में बुवाई और कटाई के चरम सीजन के दौरान कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना में 60 दिनों के विराम का प्रावधान है।
- **राज्यों द्वारा वित्त पोषण का भार साझा करना :** एमजीएनआरईजीए से हटकर, वीबी-जी आरएएम जी अधिनियम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के वित्त पोषण में राज्यों की अधिक हिस्सेदारी का प्रस्ताव करता है।

--:6::--

- एमजीएनआरईजी के विपरीत, जहां केंद्र सरकार मजदूरी बिल का 100% भुगतान करती थी, वीबी-जी आरएएमजी योजना के तहत वित्त पोषण का 40% भार राज्यों पर डाल दिया गया है।
- इसके अपवाद पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य तथा विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश (UTs) हैं, जहां केंद्र सरकार 90% वित्तीय भार वहन करेगी। जहां तक विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों की बात है, वहां पूर्ण वित्तीय भार केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- **ऊपर से नीचे तक संसाधन आवंटन का दृष्टिकोण :** इसमें राज्यों के श्रम बजट पर आधारित केंद्रीय आवंटन के एमजीएनआरईजीएस मॉडल को भी बदल दिया गया है, जिसमें अब केंद्र ही संसाधनों के हस्तांतरण का निर्धारण करता है।

Viksit Bharat G RAM G Act 2025
DIGNITY, SAFETY & SOCIAL SECURITY AT WORKSITES

WORKSITE FACILITIES – A LEGAL GUARANTEE

- Clean drinking water at every worksite
- Shade and rest areas to protect from heat
- First-aid kit at every worksite

WOMEN-FRIENDLY WORKSITES

At worksites with 5+ children below 5 years, a woman worker will be appointed for childcare and paid at the prescribed wage rate.

WORKER SAFETY & SOCIAL SECURITY

- Free medical treatment in case of accidents
- Accommodation
- Treatment
- Medicines
- Daily allowance equal to half the wage rate

In cases of death or permanent disability, ex-gratia assistance will be payable as per Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana.

TRANSPARENCY & ACCOUNTABILITY

- Mandatory Janata Boards
- Geo-tagging of assets
- Real-time dashboards
- Mobile-based monitoring
- Strengthened social audits

Source: Ministry of Rural Development

- **ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, जॉब कार्ड की जगह लेंगे:** वीबी-जी आरएएम जी अधिनियम मौजूदा एमजीएनआरईजीएस श्रमिकों के लिए निरंतरता बनाए रखता है, जिसके तहत राज्यों द्वारा नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाने तक उनके ई-केवाईसी सत्यापित जॉब कार्ड वैध रहेंगे।

Daily Current Affairs

Date : 04 July, 2026



- **समय पर भुगतान और दंड:** मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से या हाजिरी सूची बंद होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए और देरी होने पर बकाया मजदूरी का 0.05% की दैनिक दर से मुआवजा देना होगा।
- **राज्यों को मानक आवंटन :** मानक आवंटन नियमों, 2026 के लिए मसौदा उद्देश्य मापदंड के तहत, केंद्र सरकार राज्यों के बीच निधियों के वितरण के आधार के रूप में सोलहवें वित्त आयोग के क्षेत्रीय हस्तांतरण सूत्र का उपयोग करते हुए, निर्दिष्ट उद्देश्य मानदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए वार्षिक निधि आवंटन का निर्णय करेगी।
- **अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें:** वीबी-जी आरएएम जी अधिनियम, 2025 के तहत, केंद्र को अकुशल मैनुअल काम के लिए मजदूरी दरें तय करने का अधिकार है और वह विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे एमजीएनआरईजीए मजदूरी से कम न हों।
- **बेरोजगारी भत्ता:** यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो पहले 30 दिनों के लिए अधिसूचित वेतन का एक-चौथाई और उसके बाद आधा भत्ता देना अनिवार्य है।

MODEL QUESTION:

- Q. "VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत वित्तीय और संसाधन आवंटन का नया दृष्टिकोण वित्तीय संघवाद (Fiscal Federalism) की गतिशीलता को बदलता है।" समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

--8--





अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन



चर्चा में क्यों?

- जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली की अपनी पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा की।



मुख्य बिन्दु:

16वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन:

- 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन एशिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों और आर्थिक महाशक्तियों के बीच द्विपक्षीय समन्वय का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उच्च समुद्री सुरक्षा तनावों के मद्देनजर, शिखर सम्मेलन ने स्थिर और पारस्परिक रूप से लाभकारी आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है।

--:9::--

Daily Current Affairs

Date : 04 July, 2026



- द्विपक्षीय ढांचा औपचारिक रूप से जापान की अद्यतन मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक रणनीति को भारत की इंडो-पैसिफिक ओशनस इनिशिएटिव और महासागर सिद्धांत से जोड़ता है ताकि नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन किया जा सके।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा:

- **यूनिफॉर्म एंटीना समझौता:** भारत और जापान ने यूनिफॉर्म परियोजना के तकनीकी पहलुओं पर सहमति व्यक्त की, जो उनकी पहली रक्षा प्रौद्योगिकी सह-विकास पहल है।
- **2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता:** दोनों पक्षों ने 2026 के अंत से पहले टोक्यो में भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया।
- **नौसेना सहयोग:** दोनों नेताओं ने JAIMEX अभ्यासों के माध्यम से नौसैनिक संबंधों का विस्तार किया और मेक इन इंडिया के तहत नौसेना के रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।

आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाएं:

- **संयुक्त आर्थिक सुरक्षा ढांचा:** दोनों देश सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए।
- **उच्च तकनीक व्यापार सुविधा:** वे निर्यात नियंत्रणों में ढील देने, सुरक्षित प्रौद्योगिकी व्यापार को बढ़ावा देने और स्थानीय मुद्रा लेनदेन को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए।

ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन:

- **सीबीजी पहल:** भारत के 1,000 बायोगैस संयंत्रों के लक्ष्य को समर्थन देने के लिए भारत-जापान सहकारी बायोगैस फॉर ग्रोथ पहल शुरू की गई।

-:10:-



Daily Current Affairs

Date : 04 July, 2026



- **ओडिशा हरित ऊर्जा परियोजना:** ओडिशा की हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ अमोनिया उत्पादन परियोजना के लिए सहयोग की पुष्टि की गई।
- **ऊर्जा सुरक्षा सहयोग:** रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर ऊर्जा लचीलापन वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि जापान ने भारत की आईईए सदस्यता का समर्थन किया।
प्रौद्योगिकी और अवसंरचना:
- **एआई रणनीतिक संवाद:** विश्वसनीय और सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नया एआई रणनीतिक संवाद स्थापित किया गया है।
- **हाई-स्पीड रेल साझेदारी:** जापान ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और भविष्य की हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।
- **क्षेत्रीय अवसंरचना परियोजनाएं:** जेआईसीए द्वारा समर्थित उन्नत परियोजनाओं में मुंबई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बागवानी शामिल हैं।
रणनीतिक अवसर:
- **एक ट्रिलियन डॉलर के निवेश प्रवाह को गति देना:** इस शिखर सम्मेलन ने जापान को भारतीय राज्यों में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करने के लिए तैयार किया, जिससे विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को समर्थन मिला।
- **भारत-जापान सीईपीए का आधुनिकीकरण:** 15 साल पुराने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की समीक्षा करने से व्यापार में विविधता लाने और वाणिज्यिक शुल्कों को कम करने का अवसर मिलता है।
- **उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास:** जापान का समर्थन भारत के पूर्वोत्तर को बंगाल की खाड़ी और बिस्मटेक क्षेत्रों से जोड़ने वाली औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण में मदद करता है।
- **वैकल्पिक हार्डवेयर पारिस्थितिकी तंत्र का लोकतंत्रीकरण:** सकुरा साइंस एक्सचेंज के तहत सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास और लूपेक्स (चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण) जैसे संयुक्त अंतरिक्ष मिशन भारत को एकल विक्रेता प्रौद्योगिकी एकाधिकार को कम करने में मदद करते हैं।

-:11:-



Daily Current Affairs



Date : 04 July, 2026



- **श्रेणी II और श्रेणी III के लघु व्यवसायों का एकीकरण:** हाल ही में शुरू हुए भारत-जापान एसएमई फोरम से भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उन्नत जापानी कॉर्पोरेट आपूर्ति श्रृंखलाओं में सीधे एकीकृत होने का अवसर मिलता है।

Model question:

- Q. हाल ही में संपन्न 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के आलोक में, दोनों देशों के द्विपक्षीय ढांचे द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।



-:12:-



UTKARSH CLASSES |  support@utkarsh.com |  : 9829 213 213

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन



चर्चा में क्यों?

- जर्मन अभियोजकों ने यूक्रेनी राज्य अधिकारियों पर 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों पर हुए विस्फोटक हमले का आदेश देने का आरोप लगाया है।



मुख्य बिन्दु:

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन

- नॉर्ड स्ट्रीम रूस और जर्मनी के बीच एक प्रमुख प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है।
- यह बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है।
- **पाइपलाइनें** : नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2।
- **महत्त्व**:
 - यह यूरोप, विशेषकर जर्मनी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
 - यह पारगमन देशों को दरकिनार करते हुए, रूस से सीधी और विश्वसनीय गैस आपूर्ति प्रदान करता है।

MCQ

Q. नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन (Nord Stream Pipeline) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह रूस और जर्मनी के बीच प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए एक प्रमुख समुद्री पाइपलाइन प्रणाली है।
2. यह पाइपलाइन मार्ग काला सागर (Black Sea) के तल से होकर गुजरता है।
3. नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 दोनों ही यूरोप (विशेषकर जर्मनी) की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं?

- | | |
|-------------|-----------------|
| (a) केवल एक | (b) केवल दो |
| (c) सभी तीन | (d) कोई भी नहीं |

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

बोरजुली आर्द्रभूमि



चर्चा में क्यों?

- बोरजुली आर्द्रभूमि को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है।



मुख्य बिन्दु:

बोरजुली आर्द्रभूमि

- **स्थान:** सोनितपुर जिला, असम
- यह जंगली चावल (ओरिज़ा रूफिपोगोन) की कई किस्मों को आश्रय देने के लिए जाना जाता है।
- यह रोग और कीट प्रतिरोधी है और बाढ़ तथा खारे पानी की स्थितियों को सहन कर सकता है।

जैव विविधता विरासत स्थल

- ये अद्वितीय, पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिनमें समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है और इनमें कुछ विशिष्ट घटक शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च स्थानिक प्रजातियाँ, संकटग्रस्त प्रजातियों की उपस्थिति आदि।
- राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के परामर्श से जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जाएगी।
- पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चयन और प्रबंधन में राज्य सरकार को सलाह देता है।

MCQ

Q. भारत में 'जैव विविधता विरासत स्थल' (BHS) किस कानून के तहत अधिसूचित किए जाते हैं?

- (a) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (b) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- (c) जैविक विविधता अधिनियम, 2002
- (d) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 🌡️

विक्रम-1, भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट

📢 चर्चा में क्यों?

- हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने विक्रम-1 के अपने पहले परीक्षण उड़ान के प्रक्षेपण की तारीख की घोषणा की है , जिसका नाम 'मिशन आगमन' रखा गया है ।

📌 मुख्य बिन्दु:

विक्रम-1, भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट

- विक्रम-1 सात मंजिला, बहु-चरणीय कक्षीय प्रक्षेपण यान है जिसे छोटे उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **विकास:** इस रॉकेट को हैदराबाद स्थित निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा पूरी तरह से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है।
- स्काईरूट ने हाल ही में 1.1 बिलियन डॉलर से अधिक के मूल्यांकन के साथ यूनिคอร์न का दर्जा हासिल किया है।

आगमन मिशन का उद्देश्य:

- **लक्ष्य:** आगमन नामक यह मिशन वैश्विक कक्षीय प्रक्षेपण मंच पर भारत के निजी क्षेत्र के आगमन का प्रतीक है।
- **लक्ष्य कक्षा:** इस उड़ान का उद्देश्य 350 किलोग्राम तक के वजन वाले पेलोड को 60 डिग्री के झुकाव के साथ 450 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित करना है।

गगन: भारत के आकाश में सटीक नेविगेशन



चर्चा में क्यों?

- भारत ने उपग्रह नेविगेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि GAGAN (GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन) भूमध्यरेखीय क्षेत्र के लिए प्रमाणित होने वाला पहला सैटेलाइट-बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम (SBAS) बन गया है।

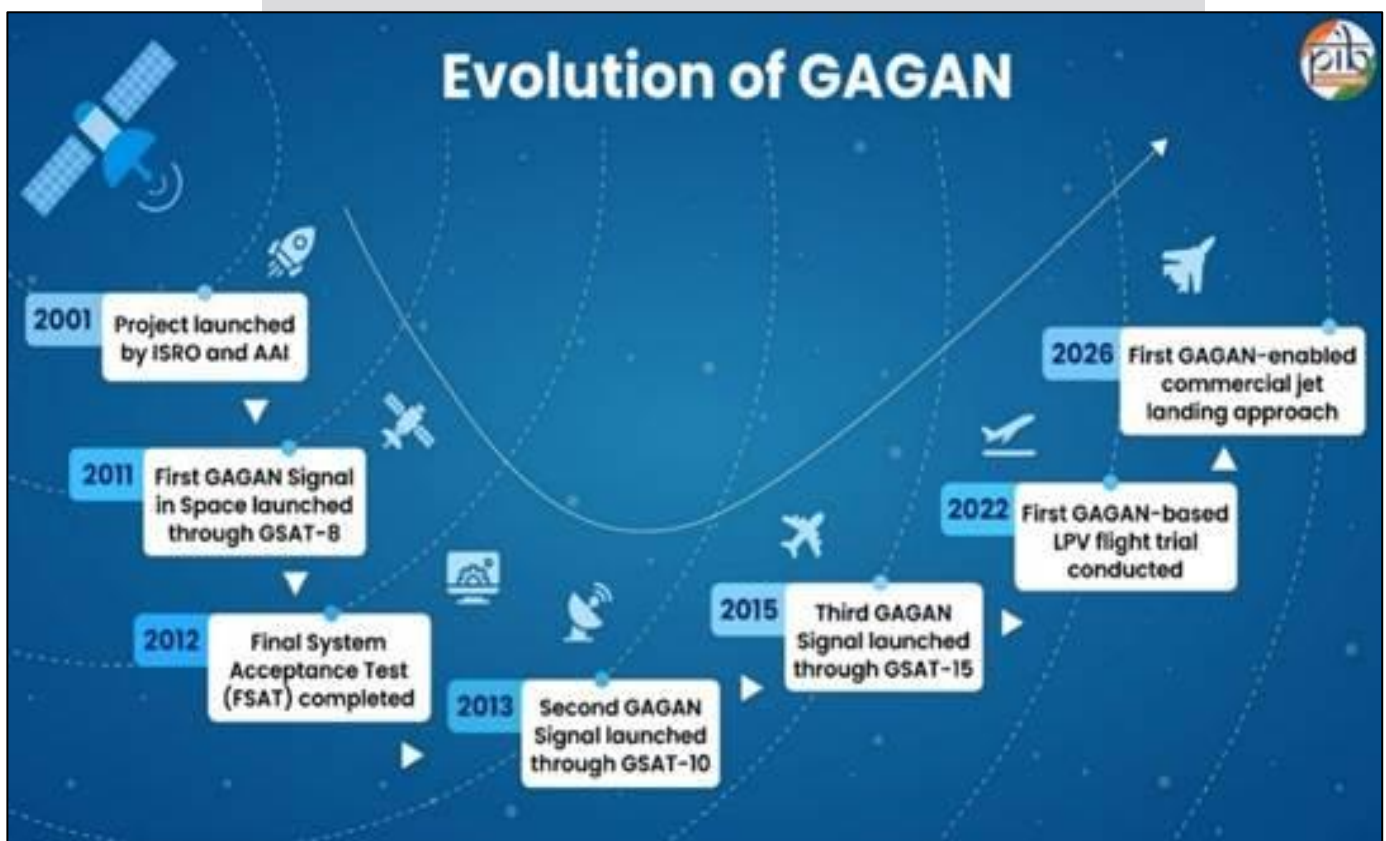


मुख्य बिन्दु:

- डीजीसीए ने हाल ही में जीएजीएन का उपयोग करते हुए एक वाणिज्यिक विमान पर भारत का पहला उपग्रह-आधारित लैंडिंग सिस्टम अप्रोच भी आयोजित किया।

गगन

- गगन भारत की स्वदेशी उपग्रह-आधारित संवर्धन प्रणाली (एसबीएस) है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- 2015 से कार्यरत यह प्रणाली वास्तविक समय में सुधार संबंधी जानकारी प्रदान करके जीपीएस संकेतों की सटीकता, उपलब्धता और अखंडता को बढ़ाती है।



--:16:--

Daily Current Affairs

Date : 04 July, 2026



महत्त्व

- भूमध्यरेखीय क्षेत्र के लिए प्रमाणित होने वाला पहला एसबीएस, जहां आयनमंडलीय गड़बड़ी उपग्रह नेविगेशन को प्रभावित करती है।
- जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
- आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत की स्वदेशी नौवहन क्षमताओं को मजबूत करता है।
- इससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास एक कार्यरत एसबीएस (सब्सिडाइज्ड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम) है।

विमानन के अलावा, GAGAN निम्नलिखित का भी समर्थन करता है:

- समुद्री नौवहन
- बुद्धिमत्तापूर्ण परिवहन और बेड़ा प्रबंधन
- रेलवे संचालन
- आपदा प्रबंधन
- रक्षा, दूरसंचार समन्वय और भू-स्थानिक मानचित्रण।

क्या आप जानते हैं ?

- GAGAN की एकीकृत डिज़ाइन भारत के व्यापक उपग्रह नौवहन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। GAGAN के साथ-साथ, भारत ने स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, नेविगेशन विड इंडियन कॉन्स्टेलेशन (NavIC) भी विकसित की है।

GAGAN (गगन)	NavIC (नैविक)
सैटेलाइट-आधारित संवर्धन प्रणाली Satellite-Based Augmentation System (SBAS)	स्वतंत्र क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली Independent regional navigation satellite system (IRNSS)
वास्तविक समय (Real-time) सुधार एवं अखंडता (Integrity) संबंधी जानकारी प्रदान करके GPS की सटीकता बढ़ाता है।	स्थिति निर्धारण (Positioning), नेविगेशन (Navigation) तथा समय (Timing) संबंधी सेवाएँ प्रदान करता है।
भारत के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन (FIR) में नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) का समर्थन करता है।	इसका कवरेज क्षेत्र भारत तथा भारतीय सीमा से लगभग 1500 किमी तक के आसपास के क्षेत्र को शामिल करता है।

-:17:-



हरित अमोनिया और मेथनॉल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में एक भारतीय कंपनी ने ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के लिए अग्रणी जापानी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक ऑफटेक समझौता किया है।

मुख्य बिन्दु:

हरा अमोनिया

- यह एक तीखी गंध वाली गैस है, जिसका मुख्य रूप से उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है।
- **उत्पादन:** हैबर-बॉश प्रक्रिया का उपयोग करके, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाया जाता है।

ग्रीन मेथनॉल

- **मेथनॉल:** एक रंगहीन तरल पदार्थ है।
- **उपयोग :** मुख्य रूप से फॉर्मेलिहाइड, एसिटिक एसिड और प्लास्टिक जैसे अन्य रसायनों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
- इसका उपयोग इंजनों के लिए ईंधन स्रोत के रूप में किया जा सकता है, लेकिन यह महंगा, ज्वलनशील भी है और इसके तेल हेतु समकक्ष की तुलना में दोगुने बड़े ईंधन टैंक की आवश्यकता होती है।
- **उत्पादन :** हरित मेथनॉल का उत्पादन बायोमास जैसे कम कार्बन वाले स्रोतों से या कार्बन कैप्चर के माध्यम से किया जाता है।